



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-Section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 208]
No. 208]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 2, 1991/चैत्र 12, 1913
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 2, 1991/CHAITRA 12, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1991

का.प्र. 232 (अ).—केन्द्रीय सरकार यह अधिनिश्चित करने की दृष्टि से यह आवश्यक समझती है कि किन आनुवंशिक और लघु औद्योगिक उपक्रमों को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (195 का 65), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम, कहा गया है) के अधीन अनुपयोगिक उपायों, छूटों या अन्य अनुकूल व्यवहार की आवश्यकता है ताकि वे अपनी अधिष्ठाता और सामर्थ्य इस प्रकार बनाए रख सकें कि वे—

- (क) देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था की सामंजस्यपूर्ण रीति से प्रीति करने और बेकारों की समस्या को सुलझाने में, और
- (ख) यह सुनिश्चित करने में कि सम्पदा के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण का वितरण इस प्रकार से किया जाए कि उससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो, प्रभावकारी हों।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11ख की उपधारा (1) और धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग द्वारा निकाली गई किसी

पूर्वतर अधिसूचना में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी उक्त धारा 11ख की उपधारा (2) में वर्णित बातों को ध्यान में रखते हुए, नीचे सारणी में वर्णित अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट कर सकेंगी जिनका किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा अनुपालन किया जाएगा ताकि उसे उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए आनुवंशिक या लघु औद्योगिक उपक्रम माना जा सके।

सारणी

I. लघु औद्योगिक उपक्रम के रूप में माने जाने के लिए औद्योगिक उपक्रम द्वारा अनुपालन की जाने वाली अपेक्षाएं।

- (क) औद्योगिक उपक्रम जिसमें संयंत्र और मशीनरी में चाहे वे स्वामित्व निबंधनों पर या पट्टे पर या अवश्य पर धारित हों, स्थिर धातुओं में विनिधान साठ लाख रुपए से अधिक नहीं है ;
- (ख) उपरोक्त (क) में विनिर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रम की वशा में संयंत्र और मशीनरी में स्थिर धातुओं में विनिधान की सीमा पचाहत्तर लाख रुपए होगी परन्तु यह तब जबकि यनिट अपना उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से तीसरे वर्ष के अन्त तक वार्षिक उत्पादन का कम से कम 30 प्रतिशत निर्यात करने का वचनबद्ध करता है।

II. आनुवंशिक औद्योगिक उपक्रम के रूप में माने जाने के लिए औद्योगिक उपक्रम द्वारा अनुपालन की जाने वाली शर्तें

ऐसा औद्योगिक उपक्रम जो पुर्ण, संगठनों, उपसमन्वयनों, उपकरणों या मध्यस्थियों के निर्माण या उत्पादन में प्रयुक्त सेवाएं देने में लगा हुआ है या लगाए जाने के लिए प्रस्थापित है और उपक्रम, एक या अधिक अन्य औद्योगिक उपक्रमों को, यथास्थिति, अपने उत्पादन या सेवाओं के पचास प्रतिशत से अधिक का प्रवाय करता है या देता है या प्रवाय करने या देने के लिए प्रस्थापित है और जिसका संयंत्र और मशीनरी में चाहे वे स्वामित्व निबंधनों पर या पट्टे पर या अक्षय्य पर धारित हों, स्थिर प्राप्ति में निनिधान पचहत्तर लाख रुपये से अधिक नहीं है।

"टिप्पणी: ऊपर निर्दिष्ट कोई भी लघु या आनुवंशिक औद्योगिक उपक्रम किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम या आनुवंशी नहीं होगा या उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन नहीं होगा।"

2. ऐसा प्रत्येक औद्योगिक उपक्रम जिसे उक्त अधिनियम के अधीन औद्योगिक विकास विभाग या तकनीकी विकास महानिदेशक द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है और अब आनुवंशिक या लघु औद्योगिक उपक्रम की उपरोक्त परिभाषा के अंतर्गत आता है, स्वामी के विवेकानुसार इस अधिसूचना के निकाले जाने की तारीख को छह मास के भीतर उस रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[काहल सं. 10/71/90-एल. पी.]

एन. आर. कृष्णन, अपर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY (Department of Industrial Development) NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 1991

S.O. 232(E).—Whereas the Central Government considers it necessary with a view to ascertain which ancillary and small scale industrial undertakings need supportive measures, exemption or other favourable treatment under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), (hereinafter referred to as the said Act) to enable them to maintain their viability and strength so as to be effective in—

- (a) promoting in a harmonious manner the industrial economy of the country and easing the problem of unemployment, and
- (b) securing that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good.

And whereas the draft notification was laid before each House of Parliament for a period of 30 days as required under sub-section (3) of section 11B of the said Act.

And whereas no modification in the proposed notification has been suggested by both Houses of Parliament.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 11B and sub-section (i) of Section 29B of the said Act, and notwithstanding

anything contained in any earlier notification issued by this Department, the Central Government hereby specifies having regard to the factors mentioned in sub-section (2) of the said Section 11B, the requirements mentioned in the Table below, which shall be complied with by the industrial undertakings to enable them to be regarded, as an ancillary, or a small scale industrial undertaking for the purpose of the said Act.

TABLE

I. Requirements to be complied with by an industrial undertaking for being regarded as small scale industrial undertaking :—

- (a) An industrial undertaking in which the investment in fixed assets in plant and machinery whether held on ownership terms or on lease or by hire purchase does not exceed rupees sixty lakhs.
- (b) In case of an industrial undertaking referred to in (a) above the limit of investment in fixed assets in plant and machinery shall be rupees seventy five lakhs provided the unit undertakes to export atleast 30 per cent of the annual production by the end of 3rd year from the date of its commencing production.

II. Requirements to be complied with by an industrial undertaking for being regarded as an ancillary industrial undertaking—

An industrial undertaking which is engaged or is proposed to be engaged in the manufacture or production of parts, components, sub-assemblies, tooling or intermediates, or the rendering of services, and the undertaking supplies or renders or proposes to supply or render not more than 50 per cent of its production or services, as the case may be, to one or more other industrial undertakings and whose investment in fixed assets in plant and machinery whether held on ownership terms or on lease or on hire purchase, does not exceed rupees seventy five lakhs.

'Note : No small scale or ancillary industrial undertaking referred to above shall be subsidiary of, or owned or controlled by any other industrial undertaking'.

2. Every industrial undertaking which has been issued a certificate of registration by the Department of Industrial Development or Director General of Technical Development under the said Act and now falls within the above definition of ancillary or small scale industrial undertaking, may be registered, at the discretion of the owner, as such, within six months from the date of issue of this notification.

3. This Notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 10(71)/90-LP]

N. R. KRISHNAN, Dd. Secy.